Dr. Vinod Baitha
Deptt. of Economics
Marwari college Darbhanga

Economics D. II Sub Lecture – 25

गरीबी की माप एवं गरीबी निवारण के उपाय

Measurement of Poverty. Programmes For removal of Poverty.

गरीबी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति न्यूनतम जीवन यापन करने में असमर्थ होता है। आधार भूत आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र, आवास की व्यवस्था नहीं कर पाना गरीबी का द्योतक है जब कोई प्रति व्यक्ति निम्नतम उपभोग व्यय स्तर से भी कम व्यय करता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। गरीब उन्हें कहा जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति परिवार व्यय के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जब निम्नतम जीवन स्तर से भी कम व्यय होता है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। जीवन स्तर के संबंध में दो धारणाओं का प्रयोग किया जाता है

1. निरपेक्ष जीवन स्तर — निरपेक्ष जीवन स्तर को बात करने के लिए अन्न, दाले, दूध, मकान इत्यादि की न्यूनतम मौलिक मात्राएँ निश्चित की जाती हैं इनकी मात्राओं के प्रयोग के आधार पर प्रति-व्यक्ति उपभोग व्यय निर्धारित किया जाता है जिस व्यक्ति या परिवार की आय इससे कम होता है उसे निर्धनता रेखा या गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है।

2. सापेक्ष जीवन स्तर — सापेक्ष जीवन स्तर का संबंध देश के विभिन्न आय वर्गों या जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की आय स्तर से होता है इनका संबंध देश में आय वितरण से भी होता है। देश के उच्च आय वर्ग के उच्चतम 5 से 10 प्रतिशत लोगों की आय की तुलना निम्न आय वर्ग के निम्नतम 5 से 10 प्रतिशत लोगों के आय स्तर से कर के सापेक्ष जीवन स्तर का अनुमान लगाया जाता है विभिन्न आय वर्गों के लोगों के बीच आय वितरण की स्थिति सापेक्ष गरीबी की स्थिति को प्रदर्शित करती है।

भारत में गरीबी से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए हैं,

Scanned by CamScanner

जिसमें पीडी ओझा डॉ० कोहरा, मिन्हास, प्रणव कुमार वर्द्धन, दांडेकर रथ, आहलुवालिया जैसे विद्वानों ने गरीबी संबंधी अध्ययन किए हैं। डी.पी. ओझा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी के मान के आधार पर मानते हैं डॉ० कोहरा ने गरीबी के तीन स्तरों की बात की है। अतिदिन. 2 दीन 3 निर्धन, मिन्हास, अहलुवालिया, तथा वर्द्धन दांडेकर तथा रथ ने भी 2250 कैलोरी उपभोग के मान को स्वीकार किया है।

वर्तमान समय में भारत में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खान पान पर शहरों में 965 रुपये और गाँवों में 781 रुपये खर्च करने वाला सख्स गरीब नहीं माना जा सकता है इससे कम खर्च करने वाले लोग गरीब माने जाएंगे। गरीबी रेखा की नयी परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा कि इसी तरह शहर में 32 रुपये और गाँव में 26 रुपये हर रोज खर्च करने वाला व्यक्ति बी.पी.एल परिवारों को मिलने वाली सुविधा का हकदार नहीं है। अपनी यह रिपोर्ट योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी। आयोग ने गरीबी रेखा पर नया क्राइटेरिया सुझाते हुए कहा कि दिल्ली, मुम्बई, बंगलोर और चेन्नई में चार सदस्यों वाला परिवार यदि महीने में 3860 रु खर्च करता है तो वह गरीब नहीं कहा जा सकता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इन्डेक्स (एस.डी.जी) 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक गरीबी मुक्त भारत के अपने लक्ष्य में चार अंक और नीचे लुढ़क गया है देश के 22 राज्य गरीबी दूर करने के बजाय और भी पीछे जा चुके हैं देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली आबादी 21 प्रतिशत पहुँच चुकी है।

भारत में गरीबी उन्मूलन, निराकरण के निम्नलिखित उपाय हैं

1. कृषि का आधुनिकीकरण तथा तीव्र विकास — कृषि आज भी देश का एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर देश की लगभग 70% जनसंख्या आश्रित है कृषि को आधुनिक बनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, सिंचाई सुविधा, भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि जोतों की चकबंदी के द्वारा कृषि विकास की गति को तेज किया जा सकता है देश में कृषि के तीव्र विकास बहुसंख्यक जनसंख्या का विकास निर्भर है गरीबी दूर करने के लिए भी कृषि का तीव्र विकास आवश्यक है।

2. प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग — देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों भरपूर तथा अनुकूलतम प्रयोग करके ही आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। इससे आर्थिक क्रियाओं का विकास होगा

Scanned by CamScanner

लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा तथा उनकी गरीबी दूर होगी।

3. देश में उद्योगों का तीव्र विकास — देश में उद्योगों के विकास की संभावना अत्यधिक है देश में प्राकृतिक साधन, खनिज, मानव शक्ति, ऊर्जा के स्रोत आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इन सभी साधनों का समुचित उपयोग किया जाय बड़े पैमाने पर उद्योगों विकास किया जाय तो उद्योगों के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों एवं कृषि आधारित उद्योगों होगा तो स्थानीय लोगों सहित अनेक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी आय बढ़ेगी अतः गरीबी दूर होगी।

4. पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि — पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि कर के विकास प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है अन्य देशों के अलावा हमारे देश में बचत तथा विनियोग दर बहुत ही कम है देश के तीव्र विकास के लिए बचत तथा विनियोग की दर को लगभग 50% करने की आवश्यकता है। पूँजी निर्माण की दर को बढ़ा कर ही विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है तथा लोगों की गरीबी को दूर किया जा सकता है।

5. जनसंख्या नियंत्रण — देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण कर के ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप दे कर कम किया जा सकता है इससे भी गरीबी दूर होगी।

6. आधारित संरचना का समुचित विकास — सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा एवं शक्ति के साधनों इत्यादि का समुचित विकास कर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर किसी भी देश का आर्थिक विकास होगा जब ये सुविधाएँ विकसित होगी तब देश का विकास भी तीव्र गति से संभव होगा। तथा देश का पिछड़ापन दूर होगी और लोगों की गरीबी मिटेगी।

7. संतुलित क्षेत्रीय विकास — देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास का अभाव रहा है। आज देश में विकास की प्रक्रिया कुछ राज्यों और क्षेत्रों तक ही सीमित है। पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है देश के संतुलित विकास द्वारा ही देश के विभिन्न वर्ग के लोगों की स्थिति में आर्थिक सुधार लाया जा सकता है।

8. उचित मानव शक्ति नियोजन तथा उत्पादक रोजगार का सृजन — देश में मानव शक्ति के लिए रोजगार सृजन की एक निश्चित योजना होनी चाहिए किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में रोजगार का सृजन करना है इसकी योजना बननी चाहिए ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त आय मिल सके। जब लोगों को रोजगार मिलेगी आय बढ़ेगी वहा गरीबी दूर होगी।

9. आय तथा धन के वितरण में व्याप्त विषमता में कमी लाना — देश में आय धन तथा परिसंपत्तियों का वितरण विषम है इससे कम करने की

Scanned by CamScanner

की आवश्यकता है धनियों पर कर लगाने की आवश्यकता है। उनकी आय का सीमा निर्धारित होनी चाहिए धनियों से प्राप्त कर को गरीबों पर खर्च कर के उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है निर्धन वर्ग के लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, की व्यवस्था भी धनी वर्ग के लोगों द्वारा होनी चाहिए इन सभी सुविधाओं के द्वारा ही निर्धनों का विकास होगा और गरीबी दूर होगी।

10. उद्यमशीलता को प्रोत्साहन — देश के लोगों में साहस, उद्यमशीलता पूँजी का विनियोग की कमी है सम्पन्न लोग अपनी पूँजी का उपयोग उत्पादन कार्यों में नहीं लगाना चाहते हैं भारत में सुविधाओं, कर छूट, तथा दूसरे तरह के प्रेरणाओं द्वारा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसा कर के देश में आर्थिक क्रियाओं का विकास, विस्तार में मदद मिलेगी तथा विकास की गति तीव्र होगी और गरीबी दूर होगी।

11. सामाजिक सेवाओं का विस्तार — देश की जनता को मूलभूत सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए तभी उनकी क्षमता एवं योग्यता का विकास होगा। प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, सफाई, जैसी मौलिक सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध होगी तभी उनका सही ढंग से विकास होगा। ड्रीज तथा सेन ने सामाजिक अवसरों की बात की है जिसमें प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर काफी बल दिया है। शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को खासकर गरीबों, दलितों, तथा महिलाओं के विकास तथा उनके सशक्तिकरण में सहायक होते हैं। उनके लिए विभिन्न तरह के अवसर तथा सम्भावनाएँ खोल देते हैं उनकी असमानता दूर करते हुए उनके विकास में योगदान करते हैं इस प्रकार गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक सुविधाओं का विकास अहम हो जाता है।

12. यातायात एवं संवादवाहन की सुविधाओं का विकास — देश में यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का विकास द्वारा देश की विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यह भी आर्थिक क्रियाओं के विस्तार द्वारा गरीबी दूर करने में मदद करेगा।

13. गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन — देश में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यथा समन्वित ग्रामीण विकास, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा आदि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हो यह सभी कार्यक्रम का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता है इसमें लाभान्वितों का गलत चयन होता, बड़े पैमाने पर साधनों की लूट होती है दलाली और दुर्गुणों के कारण गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस लिए इन योजनाओं को सही और उचित ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिससे गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस प्रकार गरीबी एक ऐसी कुप्रथा से जुड़ी हुई बीमारी है जिसका इलाज सरकारी व्यवस्था या उपर्युक्त कारणों को अपना कर दूर किया जा सकता है जिससे समाज में समरसता का माहौल बन सके और सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके।